**Prices of milk in Delhi**

1380. SHRI ISH DUTT YADAV: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is fact that a proposal is lying pending with Government to increase the prices of Milk in Delhi being supplied through DMS and Mother Dairy; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI K. C. LENKA): (a) and (b) The price of milk supplied by the Mother Dairy is determined by the Mother Dairy itself. The price of milk supplied by the Delhi Milk Scheme is determined by the Government from time to time taking into account factors like the price of raw milk and other ingredients required for constitution of the liquid milk and administrative/overhead costs incurred by the Delhi Milk Scheme.

**दिल्ली दुग्ध योजना में भ्रष्टाचार**

1381. **श्री राम जेठमलानी :**

**डा० जितेन्द्र कुमार जैन :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार, दूध की खरीद में अनियमितताओं और इसकी आपूर्ति में अकुशलता के बारे में गत कुछ महीनों में अनेक शिकायतें की गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि शिकायतकर्ताओं में एक शिकायतकर्ता "दिल्ली दुग्ध योजना" में ही कार्यरत कर्मचारियों की यूनियन ही है;

(ग) यदि हां, तो उक्त यूनियन द्वारा की गयी शिकायत का पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कराई हैं, और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?



**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी०लेंका)** (क) से (ङ) दिल्ली दुग्ध योजना में दूध की खरीद-फरोख्त/वितरण में अनियमितता बरतने, दूध के ठेके देने में पक्षपात करने, अधिकारी/कर्मचारी विशेष के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं। ये शिकायतें कभी-कभी दिल्ली दुग्ध योजना कर्मचारी संघों के नाम से भी की जाती हैं। शिकायतों की उपचारात्मक कार्रवाई के लिए जांच-पड़ताल की जाती है जिनमें जहां कहीं आवश्यक हो, मामलों का केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजना भी शामिल है।

**दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना**

1381. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देश में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना करने की अनुमति देने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने आवेदन सरकार के पास विचारार्थ लम्बित हैं; और

(ग) क्या सरकार इन संयंत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जाने के लिए कतिपय शर्तें लगाने का विचार रखती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका)** : (क) और (ख) यद्यपि विदेशी इक्विटी होल्डिंग वाली किसी कम्पनी से दूध के प्रसंस्करण तथा पैकिंग के लिए संयंत्र लगाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि ऐसी पांच कम्पनियों ने जुलाई 1991 के पश्चात्, जब से दुग्ध उत्पादों के विनिर्माण को लाइसेंस से मुक्त किया गया था, दुग्ध उत्पादों के विनिर्माण/मौजूदा क्षमता का विस्तार करने के लिए सूचना ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं।